भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3242
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

पंजाब में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

†3242. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पंजाब में कितने मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार का धान और मक्का उत्पादक जिलों के लिए नई शीत श्रृंखला अथवा मूल्यवर्धन परियोजनाओं का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गई है; और
(घ) इन पहलों से कितना रोजगार सृजित हुआ है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): इन योजनाओं की शुरुआत से अब तक, मंत्रालय ने पंजाब राज्य में 3 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं और 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में पंजाब राज्य में मेगा फूड पार्क (एमएफपी) और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) योजना के अंतर्गत कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। पंजाब राज्य में स्वीकृत मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों का विवरण और उनके कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017-18 से पूरे देश में "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" नामक केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना लागू कर रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। योजना का लक्ष्य देश में खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके इस उद्देश्य को प्राप्त करना है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत योजनाएँ मांग आधारित हैं; पंजाब राज्य सहित पूरे भारत से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत 5 सक्रिय घटक योजनाएँ हैं, जिनमें एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (आईसीसी), कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना सृजन (एपीसी), खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी), ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना [खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एफटीएल योजना)] शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय ने पंजाब राज्य में 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति, जारी की गई अनुदान सहायता राशि और रोजगार संबंधी विवरण **अनुबंध -II** में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध - I

दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु 'पंजाब में कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3242 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पंजाब राज्य में स्वीकृत मेगा फूड पार्क और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर और उनके कार्यान्वयन की स्थिति:

मेगा फूड पार्क

क्र. सं	**एसपीवी/आईए नाम**	**जिला**	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम**	**अंतिम स्वीकृति की तिथि**	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति**
01	इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क लिमिटेड	फाजिल्का	पंजाब	25-मई-11	130.38	50	45	चालू
02	सुखजीत मेगा फूड पार्क एंड इंफ्रा लिमिटेड	कपूरथला	पंजाब	06-नवंबर-15	107.83	48.7	38.76	चालू
03	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएआईसी)	लुधियाना	पंजाब	27-नवंबर-15	112.87	37.73	37.62	कार्यान्वयन के अंतर्गत

कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर

क्र. सं	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीईए) का नाम	ज़िला	राज्य	स्वीकृति की दिनांक	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये में)	कुल जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	मेसर्स एसएमएस फूड पार्क	जालंधर	पंजाब	15.03.2019	15.19	4.68	3.19	कार्यान्वयन के अंतर्गत
2	मेसर्स बिग बेली ब्रदर्स गॉरमेट ग्राउंड्स	मुक्तसर	पंजाब	08.06.2018	27.86	8.66	6.16	कार्यान्वयन के अंतर्गत
3	मेसर्स टीआर मेगा फूड्स एंड बेवरेजेज एलएलपी	फिरोजपुर	पंजाब	03.07.2019	27.44	6.75	5.14	चालू

अनुबंध - II

दिनांक 12.03.2026 को 'पंजाब में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर' के संबंध में लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3242 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31.01.2026 तक पंजाब राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति

स्वीकृत परियोजनाएँ	पूर्ण / चालू परियोजनाएँ	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	अपेक्षित प्रसंस्करण क्षमता (एलएमटी / प्रतिवर्ष)	अनुमानित परिरक्षण क्षमता (एलएमटी / प्रतिवर्ष)	रोजगार सृजन
74	62	1548.25	422.25	369.50	11.96	9.16	77088